>

Title: Need to set up a marine training academy in Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने पिछली लोक सभा में इस विषय को लगातार उठाया था। इस विषय को सदन में बार-बार उठाने के बाद के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। गुजराती में एक कहावत है **:** "बेस कानें वात अथडातीनथी" आज मैं फिर से इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। गुजरात में 1663 किलोमीटर की सामुद्रिक सीमा पड़ती है और वर्षों से गुजरात मरीन टेरर्स से जूझ रहा है। राज्य के इतने लम्बे संवेदनशील सामुद्रिक सीमा को मद्देनजर रखकर कोस्टल सिक्युरिटी फेज़ वन का काम मरीन पुलिस स्टेशन, चैक पोस्ट तथा आउट पोस्ट स्थापित किए हैं। 12 और 5 टन की बोट द्वारा कोस्टल पैट्रोलिंग की जा रही है। समग्र भारत भर में फेज़ वन का कार्य पूरा करने में गुजरात अव्वल नम्बर पर है। फेज़ टू का काम अब शुरू हो गया है। सामुद्रिक सीमा के विस्तारों में कार्य करने और ऑफशोर पैट्रोलिंग करने के लिए अलग किस्म का अनुभव जरूरी है। उनके बारे में खास प्रकार के प्रशिक्षण वाले कर्मचारियों, कोस्टल पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी बजाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप मूलभूत प्रशिक्षण देने के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा पैट्रोलिंग वोट के ऑपरेशन और मेनटेनैंस के बारे में स्पैशल कोर्स चलाने की अति आवश्यकता है जिसके लिए अलग प्रकार की तालीम, शिक्षा की जरूरत है।...(व्यवधान)

मैं एक बात कहना चाहती हूं। मरीन पुलिस एकाडमी का निर्माण करने के लिए गुजरात सरकार ने कुछ खास पुलिस अधिकारियों की टीम को राज्य की सामुद्रिक सीमा का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। जियोग्राफिकली और ट्रेनिंग के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं को मद्दे नजर रखकर गुजरात के लिए पोरबंदर-मरीन पुलिस एकाडमी के लिए अनुकूल है। राज्य सरकार ने इस एकाडमी के लिए केन्द्र की जरूरत के मुताबिक जामनगर जिले में 250 एकड़ जमीन निशुल्क देने के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है। इससे हम भारत सरकार को भी अवगत कराते हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मरीन टेरर्स से जूझ रहे गुजरात और देश की सुरक्षा की परिपूर्ति हेतु गुजरात राज्य में मरीन ट्रेनिंग एकाडमी की स्थापना की मंजूरी जल्द से जल्द दी जाए तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ठोस कदम उठाए जाएं।